



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]
No. 164]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 244(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 236

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 7 आदेश, 2008 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, “विरासत संरक्षण”— ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के परिरक्षण

और संरक्षण तथा इन स्थलों पर परिदर्शन को सुकर बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना में सुधार लाने के लिए व्यय मद्दे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	1000.00
अरुणाचल प्रदेश	125.00
असम	49.32
बिहार	1000.00
छत्तीसगढ़	246.00
गोवा	1000.00
गुजरात	625.00
हरियाणा	375.00
हिमाचल प्रदेश	250.00
जम्मू-कश्मीर	250.00
झारखंड	250.00
कर्नाटक	1250.00
केरल	625.00
मध्य प्रदेश	500.00
महाराष्ट्र	1250.00
मणिपुर	125.00
मिजोरम	125.00
नागालैण्ड	125.00
उड़ीसा	1250.00

(1)	(2)
पंजाब	250.00
राजस्थान	1250.00
सिक्किम	125.00
त्रिपुरा	125.00
उत्तर प्रदेश	1250.00
पश्चिमी बंगाल	1000.00

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,
राष्ट्रपति।”।

[फा. सं. 19(5)/2008-विधायी I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 244(E).— The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 236

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 7 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 7 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to each

of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards expenditure for “Heritage Conservation”—preservation and protection of historical monuments, archaeological sites, public libraries, museums and archives, and also for improving the tourist infrastructure to facilitate visit to these sites, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1000.00
Arunachal Pradesh	125.00
Assam	49.32
Bihar	1000.00
Chhattisgarh	246.00
Goa	1000.00
Gujarat	625.00
Haryana	375.00
Himachal Pradesh	250.00
Jammu and Kashmir	250.00
Jharkhand	250.00
Karnataka	1250.00
Kerala	625.00
Madhya Pradesh	500.00
Maharashtra	1250.00
Manipur	125.00
Mizoram	125.00
Nagaland	125.00
Orissa	1250.00
Punjab	250.00
Rajasthan	1250.00
Sikkim	125.00
Tripura	125.00
Uttar Pradesh	1250.00
West Bengal	1000.00

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”.

[F. No. 19(5)/2008-Leg. I]

K. D. SINGH, Secy.